

आयुक्त(अपील)का कार्यालय, Office of the Commissioner (Appeal),

केंद्रीय जीएसटी, अपील आयुक्तालय, अहमदाबाद Central GST, Appeal Commissionerate, Ahmedabad जीएसटी भवन, राजस्वमार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद३८००१५. CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015 207926305065 – टेलेफैक्स07926305136



THR -53

DIN: 20221264SW0000111F61

स्पीड पोस्ट

- क फाइल संख्या : File No : GAPPL/COM/CEXP/298/2022
- ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal No. AHM-EXCUS-001-APP-099/2022-23 दिनॉंक Date : 14-12-2022 जारी करने की तारीख Date of Issue 15.12.2022

आयुक्त (अपील) द्वारापारित Passed by **Shri Akhilesh Kumar**, Commissioner (Appeals)

- ग Arising out of OIO No. 03/CGST/Ahmd-South/Supdt/SSC/2022-23 दिनॉक: 29.04.2022 passed by Superintendent, Range II, CGST, Division V, Ahmedabad South
- ध अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address

Appellant

M/s Maruti Polyplast 192 & 204, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad - 382415

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन

art va tiala

Revision application to Government of India:

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप—धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

- (क) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।
- (A) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (ख) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (B) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (c) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए।उसके साथ खाता इ.का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम होतो रूपये 200/-फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपीलः— Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:--

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

- (क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण<u>(सिस्टेट)</u> की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन , असरवा , गिरधरनागर, अहमदाबाद–380004
- (a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad : 380004. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



2

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होत`हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्कअधिनियम 1970 यथासंशोधित की अनुसूचि–1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू.6.50 पैसे कान्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(69) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण<u>(सिस्टेट)</u>,के प्रतिअपीलो के मामले में कर्तव्यमांग(Demand) एवं दंड(Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है।(Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded)-

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.
- यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है.

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

(ccviii) amount determined under Section 11 D;

(ccix) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(ccx) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

ORDER-IN-APPEAL

4

The present appeal has been filed by M/s. Maruti Polyplast, 192 & 204, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad – 382 415 (hereinafter referred to as the "appellant") against Order in Original No. 03/CGST/Ahmd-South/Supdt/SSC/2022-23 dated 29.04.2022 [hereinafter referred to as "*impugned order*"] passed by the Superintendent, Range-II, Division – V, CGST, Commissionerate : Ahmedabad South [hereinafter referred to as "*adjudicating authority*"].

2. Briefly stated, the facts of the case is that the appellant were holding Central Excise Registration No. AARFM5213AEM001 and engaged in the manufacture of goods falling under Chapter Heading 39172190 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985. It was observed that the appellant had not filed ER-1 returns for the period from April, 2016 to March, 2017 as stipulated in Rule 12 of the Central Excise Rules, 2002 (hereinafter referred to as the CER, 2002). The appellant were requested vide letter dated 11.03.2020 to file the returns and furnish copy of the same along with proof of payment of duty along with interest and penalty, if any. However, the appellant neither filed the return not submitted proof of filing return. Therefore, it appeared that the appellant had contravened the provisions of Rule 12 (1) of the CER, 2002 and rendered themselves liable for penal action under Rule 27 of the CER, 2002.

3. The appellant was, subsequently, issued Show Cause Notice bearing No.AR-II/Div-V/ER-1/MP/2018-19 dated 31.12.2020 wherein it was proposed to impose penalty under Rule 27 of the CER, 2002. The SCN was adjudicated vide the impugned order and penalty amounting to Rs.3,00,000/- was imposed under Rule 12 (6) read with Rule 27 of the CER, 2002.

4. Being aggrieved with the impugned order, the appellant have filed the present appeal on the following grounds :

F No.GAPPL/COM/CEXP/298/2022

 They had already surrendered their Central Excise Registration from April, 2016 onwards. The application for surrendering the registration was done manually and their letter was duly acknowledged by the department. Copy of the letter is submitted for reference.

5. ***

ii. In terms of Rule 12 (1) of the CER, 2002, only a registered assessee was required to file ER-1 returns on the 10th day after closure of the month. They had surrendered their registration and, therefore, were not liable for furnishing returns at all. Hence the question of penalty does not arise.

5. Personal Hearing in the case was held on 09.12.2022. Shri Vipul Khandhar, Chartered Accountant, and Shri Hiralal Patel, Partner, appeared on behalf of appellant for the hearing. They submitted that they had surrendered the registration on 02.04.2016 but the department did not cancel the registration. They reiterated the submissions made in appeal memorandum.

6. I have gone through the facts of the case, submissions made in the Appeal Memorandum as well as submissions made at the time of personal hearing and the material available on records. The issue before me for decision is as whether the impugned order imposing penalty of Rs.3,00,000/-, in the facts and circumstances of the case, is legal and proper or otherwise.

7. The appellant have with their appeal memorandum submitted a copy of letter dated 01.04.2016 addressed to the jurisdictional Central Excise office wherein it has been informed that they have stopped production activity from 31.03.2016 and are surrendering their Central Excise Registration for cancellation w.e.f. 31.03.2016. The letter bears an acknowledgment of receipt dated 02.04.2016. Therefore, the appellant have contended that they were not required to file ER-1 returns.



The adjudicating authority has at Para 6 of the impugned order orded that the appellant had not filed any defence reply and at Para 7, it has been stated that the appellant did not appear for personal hearing on the three different dates given to them. Therefore, the case was adjudicated ex-parte.

6

9. In terms of Section 33A (1) of the Central Excise Act, 1944, the adjudicating authority shall give an opportunity of being heard. In terms of sub-section (2) of Section 33A, the adjudicating authority may adjourn the case, if sufficient cause is shown. In terms of the proviso to Section 33A (2), no adjournment shall be granted more than three times. In the instant case, it is observed that three adjournments as contemplated in Section 33A of the Central Excise Act, 1944 have also not been granted to the appellant. I find it relevant to refer to the judgment of the Hon 'ble High Court of Gujarat in the case of Regent Overseas Pvt Ltd. Vs. UOI - 2017 (6) GSTL 15 (Guj) wherein it was held that :

"12. Another aspect of the matter is that by the notice for personal hearing three dates have been fixed and absence of the petitioners on those three dates appears to have been considered as grant of three adjournments as contemplated under the proviso to sub-section (2) of Section 33A of the Act. In this regard it may be noted that sub-section (2) of Section 33A of the Act provides for grant of not more than three adjournments, which would envisage four dates of personal hearing and not three dates, as mentioned in the notice for personal hearing. Therefore, even if by virtue of the dates stated in the notice for personal hearing it were assumed that adjournments were granted, it would amount to grant of two adjournments would mean, in all four dates of personal hearing."

10. In view of the above, I am of the considered view that in the interest of the principles of natural justice, the matter is required to be remanded back for denovo adjudication after affording the appellant the opportunity of filing their defence reply and after granting them the opportunity of personal hearing.

11. Accordingly, the impugned order is set aside and the matter is remanded back to the adjudicating authority for adjudication afresh. The appellant is directed to submit their written submission to the adjudicating authority within 15 days of the receipt of this order. The appellant should also attend the personal hearing as and when fixed by the adjudicating

F No.GAPPL/COM/CEXP/298/2022

authority. Accordingly, the impugned order is set aside and the appeal of the appellant is allowed by way of remand.

12. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

(Akhilesh Kumar

Commissioner (Appeals) Date: 14.12.2022.



Appellant

Respondent

Attested:

(N.Suryanarayanan. Iyer) Superintendent(Appeals), CGST, Ahmedabad.

BY RPAD / SPEED POST

Τo

M/s. Maruti Polyplast, 192 & 204, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad – 382 415

The Superintendent, CGST, Range-II, Division- VI, Commissionerate : Ahmedabad South.

Copy to:

- 1. The Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone.
- 2. The Principal Commissioner, CGST, Ahmedabad South.
- 3. The Assistant Commissioner (HQ System), CGST, Ahmedabad South. (for uploading the OIA)

4. Guard File.

5. P.A. File.

